पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा की

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिले तथा सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो : मुख्यमंत्री

एम्बुलेन्स रिस्पॉन्स टाइम को और कम करें, आपात स्थिति में प्रत्येक मिनट अत्यन्त महत्वपूर्ण

मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबन्धन से सशक्त किया जाए

मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए

आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमन्द परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बन रही

पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को शामिल किया जाए

वर्ष 2016–17 की तुलना में सत्र 2025–26 तक प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 44 से बढ़कर 83 हो गई

विगत 10 वर्षों में पी0जी0 सीटों की संख्या 1,344 से बढ़कर 5,067 तथा एम0बी0बी0एस0 सीटें 5,390 से बढ़कर 12,800 तक पहुंच गई

नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत कोविड कालखण्ड में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का प्राथमिकता के आधार पर यथोचित समायोजन किया जाए

आशा वर्कर्रों का भुगतान किसी भी स्थिति में लम्बित न रहे, हेल्थ ए0टी0एम0 सेवाओं का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए

संचारी रोग नियंत्रण अभियान को और प्रभावी बनाने तथा मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश

टी0बी0 उन्मूलन अभियान को जनान्दोलन बनाया जाए तथा स्कूलों, कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे जोड़ा जाए

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक, जवाबदेही और संवेदनशीलता तीनों एक साथ दिखाई देनी चाहिए, तभी आम लोगों का भरोसा और मजबूत होगा

लखनऊ : 26 मई, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए।

साथ ही, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबन्धन से सशक्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में 108 जनपदीय चिकित्सालय, 106 विशिष्ट चिकित्सालय, 976 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3,757 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 27,668 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित हैं। वर्ष 2025–26 में सरकारी अस्पतालों में 26.41 करोड़ ओ0पी0डी0 सेवाएं और 1.23 करोड़ आई0पी0डी0 सेवाएं दी गईं तथा 24.33 करोड़ पैथोलॉजी जांचें भी की गईं। वर्ष 2016–17 की तुलना में सत्र 2025–26 तक प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 44 से बढ़कर 83 हो गई, जो 88.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। विगत 10 वर्षों में पी0जी0 सीटों की संख्या 1,344 से बढ़कर 5,067 हो गई है, जबकि एम0बी0बी0एस0 सीटें 5,390 से बढ़कर 12,800 तक पहुंच गई हैं। सुपर स्पेशियलिटी सीटों में लगभग 165 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री जी को नर्सिंग शिक्षा के विस्तार की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 652 नर्सिंग संस्थान संचालित हैं। ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य में लगभग 3.95 लाख पंजीकृत नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हैं। 'मिशन निरामया 1.0' के तहत नर्सिंग शिक्षा में हुए सुधारों की जानकारी दी गई। 17 हजार स्कूलों में परामर्श सत्र आयोजित किए गए तथा 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई गई। 10,570 नर्सिंग संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमन्द परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बन रही है। उन्होंने क्लेम दावों का तय समय–सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों को समय पर भुगतान होता रहेगा, तो मरीजों को बेहतर सुविधा मिलती रहेगी। उन्हें अवगत कराया गया कि प्रदेश में 6,480 अस्पताल योजना से जुड़े हैं और अब तक 96.75 लाख से अधिक निःशुल्क उपचार किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जी ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों की आई0पी0डी0 सेवाओं को भी योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत कोविड कालखण्ड में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का प्राथमिकता के आधार पर यथोचित समायोजन किया जाए। आशा वर्करों का भुगतान किसी भी स्थिति में लम्बित न रहे। साथ ही, हेल्थ ए0टी0एम0 सेवाओं का विस्तार करते हुए उन्हें अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जनजागरूकता, स्वच्छता और समयबद्ध उपचार व्यवस्था के माध्यम से बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला तक समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचनी चाहिए। उन्हें अवगत गया कि 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के अन्तर्गत 15.28 करोड़ से अधिक आभा आई0डी0 बनाई जा चुकी हैं। प्रदेश में 15.14 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए गए हैं। हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और लैब इन्फॉर्मेशन सिस्टम का दायरा भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि मेडिकल संस्थानों को रिसर्च आधारित स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि 'UP-IMRAS' डिजिटल पहल, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, क्लिनिकल ट्रायल यूनिट तथा मेड–टेक कार्यक्रमों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा अनुसंधान और मेड–टेक क्षेत्र में लगभग 1,500 करोड़ रुपये निवेश के लिए इंटेन्ट फाइल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं तय समय–सीमा में पूर्ण हों, ताकि आमजन को शीघ्र बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकें। बैठक में आगामी महीनों में प्रस्तावित महत्वपूर्ण लोकार्पण एवं शिलान्यास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का बहुमंजिला गर्ल्स हॉस्टल, अयोध्या मेडिकल कॉलेज का 110 बेडेड ट्रॉमा सेन्टर, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज तथा कानपुर मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग विस्तार एवं डी–एडिक्शन वॉर्ड ब्लॉक शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि सार्वजनिक–निजी सहभागिता मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जनपद महराजगंज, शामली और सम्भल में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जबकि कई अन्य जनपदों में प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि '108' एम्बुलेन्स सेवा और एडवान्स्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स की प्रतिक्रिया अवधि में लगातार सुधार हुआ है। वर्तमान में 375

ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स संचालित हैं और अब तक 9.38 लाख मरीजों को रेफर किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने एम्बुलेन्स रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने के निर्देश देते हुए कहा कि आपात स्थिति में प्रत्येक मिनट अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने एम्बुलेंस संचालकों का भुगतान समय से सुनिश्चित करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तीन माह से कम एक्सपायरी अवधि वाली दवाएं अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए और उनकी जगह नई दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 75 जनपदों में डायलिसिस सेवा और 74 जनपदों में सी0टी0 स्कैन सेवा उपलब्ध है। मार्च 2026 तक 35.69 लाख से अधिक डायलिसिस सत्र और 45.35 लाख से अधिक सीटी स्कैन किए जा चुके हैं। 227 सी0एच0सी0 पर टेली–रेडियोलॉजी सेवा संचालित है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री जी को अगवत कराया गया कि संस्थान में 376 से अधिक रोबोटिक सर्जरी तथा 250 से अधिक किडनी प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। यहां प्रदेश का पहला गामा नाइफ सेंटर स्थापित किया जा रहा है। लोहिया संस्थान के नए परिसर में 1,010 बेड क्षमता वाले अत्याधुनिक चिकित्सालय के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। वहीं एस0जी0पी0जी0आई0 में 500 बेड एडवान्स पीडियाट्रिक सेन्टर परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।

बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर मिशन, यू0पी0 ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क (UPTEN), प्रोजेक्ट सुश्रुत तथा CARE-UP मिशन की कार्ययोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री जी को अगवत कराया गया कि UPTEN के तहत प्रदेश में आपातकालीन ट्रॉमा नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जबकि CARE-UP मिशन के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में आई0सी0यू0 एवं एच0डी0यू0 सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने टी0बी0 उन्मूलन अभियान को जनान्दोलन बनाने पर बल देते हुए कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि 100 दिवसीय टी0बी0 मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संविदा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बेहतर चिकित्सक सरकारी सेवाओं से जुड़ें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक, जवाबदेही और संवेदनशीलता तीनों एक साथ दिखाई देनी चाहिए, तभी आम लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।